जोशी, वाजपेयी और नायडू को बी.एच.यू. द्वारा मानद उपाधियां

कुर्सी बचाने की कुलपति की कोशिश और शिक्षा में संघी घुसपैठ की मुहिम का बदबूदार मेल

कृष्णगोविन्द सिंह

अभी हाल ही में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी बाजपेयी और चन्द्र बाबू नायडू को मानद डाक्टर उपाधियां दीं। अचानक हिन्दुत्व के इन महारथियों को मानद डिग्रियां बांटने का विचार कुलपति महोदय को कहां से आया? और किन उपलब्धियों के एवज में ये डिग्रियां बांटी गयीं?

दरअसल, अपनी डगमगाती कुर्सी को संभाले रखने के लिए कुलपति एस.वाई सिम्हाद्रि ऐसे लोगों को मानद उपाधियों की रेवड़ियां बांट रहे हैं जो उनकी कुर्सी को बचाने में उनकी मदद करें। मुरली मनोहर जोशी को मानद डाक्टर आफ साइन्स की उपाधि देने के पीछे यह कारण बताये गये हैं– **'डा. जोशी श्री राम की जन्मभूमि में महान मंदिर के निर्माण हेतु सतत् सक्रिय रहे हैं, जिसका हमारी धार्मिक परम्पराओं और गरिमा के सामाजिक प्रतीकों के सन्दर्भों में परमोच्च महत्ता का स्थान है और जो प्रभावशाली मानवीय और अति मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।'** इसके अलावा गौरक्षा आन्दोलन में भाग लेने और अल कबीर बूचड़खाने को बन्द कराने के लिए सत्याग्रह में भाग लेने को भी कारणों की सूची में जोड़ा गया है। बी.एच.यू. के बुद्धिजीवियों, अध्यापकों और छात्रों ने कुलपति के निर्णय का भारी विरोध किया।

जोशी के बाद बारी आयी प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। बाजपेयी के एल. एल.डी. और नायडू की डी.लिट् की डिग्रियां दी गयीं।

मानद उपाधियों की रेवड़ियों के बंटने का सिलसिला यहीं नहीं थम जाता। विश्वविद्यालय का 'विजिटर' राष्ट्रपति होता है सो, राष्ट्रपति के सचिव गोपाल गांधी को मानद उपाधि दी गई। बी.एच.यू. में मानवाधिकार उल्लंघन के आधा दर्जन मामले मानवाधिकार आयोग में चल रहे हैं सो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.एस.वर्मा को मानद एलएल.डी. दे दी गयी। क्या आपने सुना है कि किसी विश्वविद्यालय ने अपने ही कार्य परिषद के सदस्य को मानद उपाधि दी हो? अगर नहीं तो लीजिए सुनिए—बी.एच.यू. के एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य प्रो. देवेन्द्र शर्मा को भी बी.एच.यू. से मानद उपाधि मिली है।

असल में दिल्ली में विपक्षी दलों से जुड़े कुछ पूर्व छात्र नेताओं और कुछेक सांसदों ने जो परिस्थितियां तैयार कर दीं हैं उससे प्रो. सिम्हाद्रि स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। वे राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों को उपाधियां देकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे परिसर में जनवादी शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और छात्रों में उनके विरुद्ध जबर्दस्त असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। बी.एच.यू. के एक शिक्षक बी.एस. कट्ट के लापता होने के मामले में भी कुलपति की भूमिका चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रो. कट्ट ने कुलपति की निरंकुशता,

भगवा पाठ्यपुस्तकों की एक बानगी

संघ कबीले ने शिक्षा जगत में तथ्यों के साथ छेड़खानी करते हुए जिस प्रकार तोड़-फोड़ मचायी है उसका उदाहरण उनके शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई तमाम पाठ्यपुस्तकों में मिल जायेगा। महज कुछ बानगियां ही उनके उद्देश्यों का, शिक्षा की उनकी अवधारणा का खुलासा करने के लिए काफी हैं।

उत्तरप्रदेश में जब पहली बार भाजपा सरकार गठित हुई तो उनके निर्देशन में छपी इतिहास की एक पाठ्यपुस्तक में 'प्रामाणिक' तौर पर यहां तक लिखा गया कि "बाबर के स्थानीय अधिकारी मीर बाकी ने अयोध्या में मन्दिर तोड़कर प्राप्त स्थान पर एक मस्जिद बनायी। यद्यपि यह इमारत विवादास्पद है पर हिन्दू जनता इसे मन्दिर मानती है।"

संघ कबीले के शिक्षा प्रकोष्ठ विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों और भाजपा शासित सरकारी स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों पर गौर करें:

भारत की 'आजादी की लड़ाई का इतिहास' बताते हुए एक पाठ्यपुस्तक में कहा गया है, "सैकड़ों बर्बर राक्षसों ने हमारे देश की ओर ललचाई निगाहों से देखा है। अनगिनत लुटेरे आक्रमणकारी अपनी विशाल सेना के साथ यहां आये। कुछ ने हिन्दू धर्म को समाप्त करना चाहा पर वे स्वयं ही समाप्त हो गये और फेंक दिये गये। इसके बार वैसे आक्रमणकारी आये जिनके एक हाथ में तलवार थी दूसरे में कुरान। असंख्य हिन्दुओं को तलवार के जोर से मुसलमान बनाया गया। आजादी की यह लड़ाई एक धर्मयुद्ध बन गई। असंख्य लोगों ने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी। पर हम अपने से अलग हुए भाइयों को पुनः हिन्दू धर्म में वापस न ला पाये।"

एक अन्य पाठ्यपुस्तक कहती है :

"मुहम्मद गोरी ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया। उसने विश्वनाथ मंदिर और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को मस्जिद में तब्दील कर दिया।" एक अन्य जगह लिखा गया है : "बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, पर्दा, जादू-टोना, और अंधविश्वास—ये सब मुसलमानों के डर के कारण थे'।

समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और नैतिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों में इस तरह के नमूने जगह-जगह देखने को मिलते हैं : "सती एक राजपूत परम्परा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए।" "आरक्षण को सामाजिक समानता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। आरक्षण ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है।" "बाल विवाह युवाओं में नैतिक पतन को रोकता है और उन्हें यौन अपराधों की ओर जाने नहीं देता।" "किसी जाति के लोग केवल अपनी ही जाति में शादी करते हैं। इससे उनके रक्त की शुद्धता बनी रहती है एवं उनके रक्त में दूसरी जाति के रक्त की अशुद्धियां नहीं आ पाती हैं।"

विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितता और अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रो. कट्ट की पत्नी ने इस घटना के पीछे प्रशासन के हाथ होने का शक जताया है। इन सारी परिस्थितियों से, जो उनके खिलाफ जा रही हैं, निपटने के लिए ही कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्यों से लेकर राजनीतिज्ञों, और विजिटर के सचिव तक पर मानद उपाधियों की बारिश कर रहे हैं।

अपना अस्तित्व बचाने की कुलपति महोदय की इस मजबूरी और अकादमिक संस्थानों में भगवा घुसपैठ की भाजपाई मुहिम के मेल से आज बी.एच.यू. का शैक्षणिक वातावरण बेहद घुटनभरा हो चुका है। छात्रों-शिक्षकों-कर्मचारियों में प्रशासन की निरंकुशशाही का आतंक जमाने की नित नयी-नयी कोशिशें होती रहती हैं। छात्र संघ निलम्बित किया जा चुका है और अधिकांश छात्र नेताओं का निष्कासन हो चुका है। आज परिसर में आम छात्रों की कोई मजबूत संगठित आवाज मौजूद नहीं है, नतीजतन आम छात्र प्रशासन की कारगुजारियों का मूकदर्शक बना हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैये का विरोध करने वाले चुनावी छात्र नेता और पूंजीवादी चुनावी पार्टियों से जुड़े हुए छात्र संगठन अपनी अवसरवादिता के कारण आम छात्रों में विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनके संघर्षों में आम छात्रों की शिरकत लगभग नगण्य है। घोर अवसरवादिता और सुविधापरस्ती की शिकार शिक्षक राजनीति भी आज नखदन्त हीन हो चुकी है। कर्मचारी राजनीति की भी यही दशा है। इसलिए प्रशासन को कोई प्रभावी चुनौती नहीं मिल रही है। इस परिस्थिति में, निष्कण्टक होकर वह तमाम छात्र-शिक्षक- कर्मचारी विरोधी कदमों को लागू करता जा रहा है। हर मुमकिन रास्ते से विश्वविद्यालय में संघी घुसपैठ लगातार जारी है।

परिसर में व्याप्त जड़ता और विकल्पहीनता की इस विकट स्थिति को तोड़ने के लिए संवेदनशील एवं बहादुर छात्रों की साहसिक एवं सृजनात्मक पहलकदमी की जरूरत है। जब तक यह पहलकदमी नहीं होती हालत बदतर ही होते जायेंगे। यह पहलकदमी कब होगी इसके बारे में शायद ठीक-ठीक बताना सम्भव न हो लेकिन देर-सबेर यह होगी जरूर, क्योंकि जहां दमन होता है, प्रतिरोध के स्वर भी वहीं मुखरित होते हैं। ●

सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को साम्प्रदायिक रंग में रंगने की कुचेष्टाएं

(पृष्ठ 23 का शेष)

उसके अनुषांगिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पचास वर्ष पूरे होने पर दूरदर्शन से विशेष कार्यक्रम तक प्रसारित करवाये।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से ही फासीवाद के खिलाफ संघर्षरत और एक लम्बी गौरवशाली परम्परा वाले 'भारतीय इतिहास कांग्रेस' में भी संघ कबीला जब-तब सेंध मारने की असफल कोशिश करता रहा है। 1989 में गोरखपुर में आयोजित इतिहास कांग्रेस पर कट्टरपंथियों द्वारा कब्जा जमाने की नापाक कोशिशें तथा 1991 में उज्जैन कांग्रेस को मध्यप्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा असफल करने की साजिशों को इसी रोशनी में देखा जा सकता है। बाबरी मस्जिद/रामजन्म भूमि विवाद को "साक्ष्यों" से परिपूर्ण करने और इतिहास के लिए "आस्था का प्रश्न" प्रधान बना देने की गरज से 'भारतीय इतिहास और संस्कृति सोसायटी' का अस्सी के दशक में संघी इतिहासकारों द्वारा पुनर्गठन एवं संघ पोषित 'इतिहास संशोधक मण्डल' की स्थापना जैसे ढेरों प्रयास इन कट्टरपंथियों द्वारा लगातार जारी हैं। इस दिशा में अपने ताजा प्रयासों के तहत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को भी संघ परिवार के 'पुरातत्वविदों' ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुरातात्विक उत्खनन एवं सर्वेक्षण की स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को ठेंगा दिखाते हुए अपनी विशिष्ट "इतिहास-दृष्टि" से उत्खनन एवं सर्वेक्षण में जुट गये हैं।

यह तथ्य भी अब सर्वविदित है कि 1990 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पाठ्यक्रमों में कितने बड़े पैमाने पर फेरबदल किा गया था! भाजपा शासित इन राज्यों की पाठ्यपुस्तकों में पौराणिक विश्वासों को 'तथ्यात्मक इतिहास' के रूप में शामिल किया गया था। इन्हीं प्रक्रियाओं के अगले क्रम में कई विश्वविद्यालयों में संघ काडर के लोगों की भरती हुई और अपने कुलपति बैठाये गये। 'वन्देमातरम' को लेकर विवाद शुरू करने के पीछे की भी इनकी कुचेष्टा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों में सरस्वती के चित्र को सामने रखकर प्रार्थना करना अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर उठे विवाद और आपसी अन्तरविरोध के कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की घटना किसी से छिपी नहीं है।

इतिहास को सिर के बल खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास विगत डेढ़ दशक से जारी है, आज वह एक खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे पुरातनपंथियों द्वारा समाज को एक बार फिर इतिहासविहीन युग की ओर ढकेला जा रहा है। भाजपा सरकार देश के सामाजिक- सांस्कृतिक ताने-बाने को हिन्दू फासिस्ट साम्प्रदायिक रंग में रंगने के हर अवसर का, हर माध्यम का उपयोग बखूबी कर रही है। कहने की जरूरत नहीं कि इनकी छापों का समाज पर जो प्रभाव पड़ा है, वह इनके सत्ता में न रहने पर भी फासिज्म को खाद-पानी देता रहेगा।

इतिहास के इस कठिन अंधेरे दौर में अंधराष्ट्रवादी फासिस्ट शक्तियों के इन सांस्कृतिक-वैचारिक हमलों से एक बार फिर जनपक्षधर, इतिहास निर्माता शक्तियों को सचेत होना होगा। इस विषाक्त वृक्ष की टहनियों पर नहीं इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। इतिहास को चाहे धूल और राख की जितनी भी परतों से ढकने की कोशिश की जाये, सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सच यही है कि इतिहासद्रोही ऐसी फासिस्ट शक्तियां अतीत में भी कूड़ेदान में फेंकी जा चुकी हैं और भविष्य के लिए भी इनके वास्ते माकूल सजा मुकर्रर हो चुकी है, जब जनता का तूफान उठेगा और इनके ताबूत में अन्तिम कील ठोंक देगा। ●

'संस्कृति के ठेकेदारों' के बढ़ते फासिस्ट हमले

(पृष्ठ 23 का शेष)

चाहे "भारतीय संस्कृति" की "रक्षा' के नाम पर ये विध्वंसक कार्रवाइयां हों या आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और मथुरा के क्रिश्चियन अध्यापक की नृशंस हत्या की घटना हो अथवा 'आह्वान कैम्पस टाइम्स' के कार्यालय पर आधी रात में सादी वर्दीधारी पुलिसिया छापामारी की घटना; ये नये दौर के फासीवादी उभार का ही द्योतक है। हिन्दूवादी साम्प्रदायिक फासिस्ट ताकतें अब अपने पूरे रंग में आने लगी हैं। इसलिए, इनका वैचारिक-सांस्कृतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भौतिक शक्ति संगठित कर मुकाबला करने की तैयारियों को तेज कर देना होगा। ●